प्र.मंत्री मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन ने अपने आधिकारिक आवास पर प्र.मंत्री मोदी को यह सम्मान प्रदान किया

■ **रूस ने प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान दोनों देशों के आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उनके असाधारण योगदान के लिए दिया है।**

■ **बैठक के दौरान रूसी राष्ट्रपति ने अपने वक्तव्य में रूस-भारत संबंधों में विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझीदारी की सराहना की। उन्होंने जिक्र किया कि पिछले साल रूस और भारत के बीच व्यापार 66 प्रतिशत बढ़ गया है और इस वर्ष की पहली तिमाही में आपसी व्यापार में 20 प्रतिशत की और बढ़ोतरी हुई है।**

मॉस्को, 9 जुलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू एपोसल पुरस्कार से सम्मानित किया। यह रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। प्र.मंत्री मोदी को दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने की दिशा में असाधारण सेवाओं के लिए इस सम्मान से नवाजा गया। उन्होंने एक समारोह में पुरस्कार प्राप्त करने के बाद एक्स पर लिखा, 'ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोसल पुरस्कार प्राप्त करके सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मैं इसे भारत की जनता को समर्पित करता हूं।'

रूस में प्र.मंत्री मोदी को सम्मानित किए जाने का वीडियो क्लिप सामने आया है। इसमें मोदी को राष्ट्रपति पुतिन कुछ समझाते नजर आ रहे हैं। पहले वह उन्हें ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू एपोसल का आगे की दिखाते हुए इशारा करते हैं। इसके बाद उन्हें पीछे की तरफ कुछ दिखाते हैं। इस दौरान मोदी को पुतिन उन्हें मिले सम्मान में लगे खास तरह के संकेतों का मतलब बता रहे होते हैं। मालूम हो कि साल 1698 में यीशू के प्रथम प्रचारक और रूस के संरक्षक संत सेंट एंड्रयू के सम्मान में जार पीटर द ग्रेट की ओर से स्थापित 'ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोसल' रूस का सर्वोच्च राजकीय सम्मान है।

इससे पहले प्र.मंत्री मोदी की रूस के राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन से लंबी बातचीत हुई। इस दौरान उन्होंने अपील की कि यूक्रेन के युद्ध में मासूमों की मौत बहुत ही पीड़ाजनक होती है। युद्ध भूमि से समाधान नहीं निकला करते हैं, इसलिए संवाद और कूटनीति के माध्यम से समाधान खोजे जाने चाहिए। मोदी ने भारत और रूस के बीच 22वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान यह बात खुल कर कही। पुतिन ने यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के सुझावों की सराहना की। बैठक में दोनों देशों ने किफायती ऊर्जा, उर्वरक व परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने का संकल्प लिया। बैठक में भारत ने रूस में आतंकवाद की घटनाओं की कड़ी निंदा की।बैठक के दौरान रूसी राष्ट्रपति ने अपने वक्तव्य में रूस-भारत संबंधों में विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझीदारी की सराहना की। उन्होंने जिक्र किया कि पिछले साल रूस और भारत के बीच व्यापार 66 प्रतिशत बढ़ा। 2024 की पहली तिमाही में 20 प्रतिशत और बढ़ गया। पुतिन ने कहा कि रूस और भारत अंतरराष्ट्रीय मामलों में निकटता से सहयोग करते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी को रुस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। रुस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन ने "सेन्ट एन्ड्र्यू द अपॉस्टल" सम्मान मोदी को प्रदान किया। यह सम्मान प्र.मंत्री मोदी को दोनों देशों के आपसी रिश्तों को बढ़ावा देने में असाधारण भूमिका निभाने के लिए दिया गया।

जे.डी.यू. केन्द्रीय बजट से 30 हजार करोड़ रु बिहार को देने की मांग कर रही है

मोदी सरकार के सबसे बड़े साथी- टी.डी.पी. ने भी 12 बिलियन डॉलर की भारी रकम की मांग की है, आंध्र प्रदेश के लिए

■ **एन.डी.ए. के दोनों गठबंधन दलों की मांगों को मिला दे तो यह सरकार के वार्षिक खाद्य सब्सिडी बजट 2.2 ट्रिलियन रुपये के आधे से भी ज्यादा के बराबर है। इससे यह साफ पता चलता है कि मोदी पर राजकोषीय दबाव बढ़ गया है।**

नई दिल्ली, 9 जुलाई। केंद्र सरकार आगामी 23 जुलाई को संसद में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश करेगी। इस बजट को जारी करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने सरकारी कर्ज पर अंकुश लगाते हुए सभी राज्यों की सरकार की मांगों को संतुलित करना होगा। जानकारों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्र में सरकार में शामिल नीतीश कुमार बिहार में परियोजनाओं के लिए मदद के लिए केंद्रीय बजट से 30,000 करोड़ रुपये की मांग कर रही है। यह गठबंधन सरकार के लिए एक परीक्षा साबित हो सकती है। मामले से जुड़े लोगों ने बताया कि जनता दल (यूनाइटेड) के नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने पिछले महीने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट-पूर्व बैठक के दौरान यह मुद्दा उठाया था।

एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार को बिहार से इस संबंध में अनुरोध प्राप्त हुआ है, लेकिन अभी तक यह तय नहीं किया गया है कि इस साल राज्य को कितना बजट आवंटित किया जाएगा।

ब्लूमबर्ग न्यूज़ ने पिछले सप्ताह के रिपोर्ट की माने तो केंद्र की गठबंधन सरकार में मोदी के सबसे बड़े साथी- तेलुगु देशम पार्टी के एन चंद्रबाबू नायडू ने भी भारी रकम की मांग की है। टीडीपी ने आंध्र प्रदेश के लिए अगले कुछ सालों में 12 बिलियन डॉलर से अधिक की सहायता के लिए अनुरोध किया है। दोनों गठबंधन दलों की मांगों को मिला दे तो यह सरकार के वार्षिक खाद्य सब्सिडी बजट 2.2 ट्रिलियन रुपये के आधे से भी ज्यादा के बराबर हैं। इससे यह साफ पता चलता है कि मोदी पर राजकोषीय दबाव बढ़ गया है। प्र.मंत्री पर अपने साथियों की मांगों के साथ साथ सरकारी लोन में कमी ला कर संतुलन बनाने का भी दबाव है। हालांकि रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को इस बार रिकॉर्ड मुनाफा देने और टैक्स कलेक्शन में वृद्धि के बाद इस साल के बजट में सरकार के पास कुछ छूट है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में बीजेपी पूर्ण बहुमत का आंकड़ा नहीं छू सकी और सरकार बनाने के लिए जदयू और टीडीपी के समर्थन पर निर्भर है। बीजेपी के दोनों सहयोगी चाहते हैं कि केंद्र सरकार उन्हें अपने राज्यों में अधिक उधार लेने की इजाजत दे।

सचिन पायलट ने टोंक...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ही बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति हो, उसके कहने पर अगर सरकार आंख मूंद लेगी और यह गैर कानूनी कार्रवाई होती रहेगी तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।

कश्मीर के कठुआ में सेना पर हुए आतंकी हमले पर उन्होंने कहा कि इस प्रकार की आतंकी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। सब भी बालिकाओं की पढ़ाई के हित में दूंगा। उन्होंने कहा कि बालिकाओं की शिक्षा के लिए किसी भी तरह के साधन संसाधनों की कमी नहीं आने दूंगा। लोकार्पण कार्यक्रम में सांसद हरीश चंद्र मीणा ने कहा कि शिक्षा विकास का सबसे बेहतर माध्यम है। बालिकाओं की शिक्षा में उनकी ओर से भी हर संभव मदद की जाएगी। इस मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष हरिप्रसाद बैरवा, पूर्व

■ **बालिका सीनियर सैकेण्डरी स्कूल कोहना के भवन का निर्माण विधायक कोटे की राशि से हुआ है, जिसकी लागत 4 करोड़ 49 लाख थी। विद्यालय के प्रिंसिपल ने दिव्यांगों के लिए लिफ्ट, सी.सी.टी.वी. कैमरे, वॉटर कूलर सहित पायलट को स्कूल के लिए आवश्यक बीस बिंदुओं की सूची दी। पायलट ने सभी कार्यों को अपने विधायक मद से पूरा कराने की घोषणा करते हुए कहा कि, टोंक के विकास के लिए, विशेषकर शिक्षा विभाग के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।**

सचिन पायलट ने 4 करोड़ 49 लाख की लागत से बने राजकीय बालिका सीनियर सैकेण्डरी स्कूल कोहना के लोकार्पण समारोह में कहा कि साढ़े चार करोड़ की लागत से यह स्कूल भवन बना है। स्कूल में और भी आवश्यक सामान व सुविधाओं बीस बिंदुओं की लिस्ट प्रिंसिपल ने दी है। वो विधानसभा उपाध्यक्ष रामनारायण मीणा,घासी लाल चौधरी, नगर परिषद चैयरमेन अली अहमद, रामलाल संडीला, पार्षद सुनील बंसल, हंसराज गाता, मूलचंद बैरवा, सरपंच संघ जिलाध्यक्ष मुकेश मीणा, धर्मेन्द्र सालोदिया, खालिद खान, नईम अपोलो इत्यादि कार्यकर्ता व ग्रामीण मौजूद थे।

ए.डी.जे...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लेकर हाईकोर्ट की परीक्षा सेल को योग्य विधिवेत्ताओं व प्रोफेसरों की कमेटी बनाने का निर्देश दिया गया था। हाईकोर्ट ने कमेटी को भी निर्देश दिए थे कि वह प्रश्न पत्र की लंबाई व प्रश्न हल करने को देखने के लिए स्वतंत्र रहेगी और हाईकोर्ट की परीक्षा सेल चार्ट के जरिए कॉपियों में कमेटी की ओर से दिए गए अंक और मौजूदा अंकों का तुलनात्मक अध्ययन कर हाईकोर्ट को बताएगी। इसे हाईकोर्ट प्रशासन ने एस.एल.पी. के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और कहा कि ए.डी.जे. भर्ती परीक्षा में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है और कमेटी की रिपोर्ट में भी परीक्षा को सही होना बताया है। गौरतलब है कि ए.डी.जे. भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर अभ्यर्थी प्रदीप मलिक व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि भर्ती परीक्षा के पेपर ज्यादा लंबे थे और साक्षात्कार में चार गुणा अभ्यर्थियों की बजाय केवल चार अभ्यर्थियों को ही बुलाया गया, जबकि भर्ती में 779 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए योग्य माना गया था। इसलिए पात्र अभ्यर्थियों को बोनस अंक देकर वकील कोटे के सभी खाली 81 पदों को भरा जाए।

कांग्रेस प्र.मंत्री मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही शुरु करने की मांग करेगी

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया है

■ **दरअसल, प्र.मंत्री मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए गत 2 जुलाई को लोकसभा में कहा, 'चाहे विपक्ष कितनी भी संख्या का दावा करे, जब हम 2014 में आए तो राज्यसभा में हमारी ताकत बहुत कम थी। साथ ही, सभापति का झुकाव कुछ हद तक दूसरी तरफ था, लेकिन हम गर्व के साथ देश की सेवा करने के अपने संकल्प से नहीं डिगे।**

नई दिल्ली, 9 जुलाई। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने इसे लेकर प्र.मंत्री मोदी के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही शुरू करने की मांग की है। उन्होंने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को पत्र भी लिखा है। रमेश ने यह चिट्ठी सोशल मीडिया मंच एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, 'नॉन-बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने घटते कद को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच, मैंने राज्यसभा के माननीय सभापति को पत्र लिखकर राज्यसभा के पूर्व सभापति डॉ. हामिद अंसारी के खिलाफ उनके अपमानजनक बयान के लिए विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने 2 जुलाई 2024 को लोकसभा में वह बयान दिया था।'

जयराम रमेश ने पत्र में दावा किया कि जिस तरह प्र.मंत्री मोदी ने अंसारी पर हमला किया, उस तरह अब तक किसी भी प्रधानमंत्री ने किसी पूर्व लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के पूर्व सभापति के खिलाफ निशाना नहीं साधा था। राज्यसभा सदस्य ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ अपने पद की गरिमा को निचले स्तर पर ले गए हैं, बल्कि उन्होंने संसदीय मर्यादाओं और नियमों को भी तोड़ा है। उन्होंने धनखड़ के सामने अपील रखी कि इस अपमानजनक टिप्पणी के लिए प्रधानमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही शुरू की जाए। मालूम हो कि प्र.मंत्री मोदी ने किसी का नाम नहीं लिया था, मगर पूर्व उपराष्ट्रपति अंसारी अगस्त 2012 से अगस्त 2017 तक राज्यसभा के सभापति रहे।

दरअसल, प्र.मंत्री मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए कुछ अहम बातें कही थीं। उन्होंने 2 जुलाई को लोकसभा में कहा, 'चाहे विपक्ष कितनी भी संख्या का दावा करे, जब हम 2014 में आए तो राज्यसभा में हमारी ताकत बहुत कम थी। साथ ही, सभापति का झुकाव कुछ हद तक दूसरी तरफ था, लेकिन हम गर्व के साथ देश की सेवा करने के अपने संकल्प से नहीं डिगे। मैं देश की जनता को कहना चाहता हूं कि आपने जो फैसला लिया है, आपने हमें सेवा करने का जो आदेश दिया है, ऐसी किसी भी बाधा से न तो मोदी डरेगा और न ही यह सरकार डरेगी। हम जिन संकल्पों को प्राप्त करने के लिए निकले हैं, उन्हें पूरा करके रहेंगे।'

भजनलाल सरकार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

को अपना पूर्ण बजट यानी परिवर्तित बजट विधानसभा में पेश करने जा रही है। पिछली चार सरकार के कार्यकाल को देखें तो केंद्र सरकार के बजट पेश होने का बाद प्रदेश का बजट पेश होता है, लेकिन इस बार भजन लाल सरकार केंद्र सरकार से पहले बजट पेश करने जा रही, क्योंकि केंद्र सरकार 20 जुलाई के बाद अपना बजट पेश करेगी। ऐसे में अगर भजन लाल सरकार केंद्र के बाद में बजट पेश करती है तो 31 जुलाई से पहले बजट सदन से पारित होकर राज्यपाल से अनुमोदित नहीं हो पाएगा, यही वजह है प्रदेश सरकार केंद्र से पहले 10 जुलाई को बजट पेश करेगी। इस बजट से आम और खास सभी को खासा उम्मीदें हैं। बताया जा रहा है कि इस बार सरकार का बजट महिलाओं पर केंद्रित होगा, इसके साथ ही रोजगार के रास्ते कैसे खोले जाए इसको लेकर भी बजट में कुछ विशेष घोषणाएं की जा सकती है। दरअसल, बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और वित्त मंत्री के तौर पर उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने अलग-अलग वर्ग के लोगों के साथ में बजट पूर्व संवाद करके बजट के संबंध में जो सुझाव लिए थे उनका असर बजट में देखा जा सकता है।

'कहीं ऐसा ना हो कि भारत को पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में उतरना पड़ जाये'

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ते हुये कहा कि, आतंकवाद बंद हो जाना चाहिये नहीं तो पाकिस्तान बर्बाद हो जायेगा

नई दिल्ली, 9 जुलाई। कठुआ में सेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले के बाद जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा है। भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत की वकालत करने वाले अब्दुल्ला ने खुलकर कहा है कि आतंकवाद और बातचीत साथ में नहीं हो सकती। पहले इसे बंद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जैसे देश पर पूरी दुनिया को दबाव बढ़ाना चाहिए कि वह आतंकवाद को बंद करे वरना बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर इसी तरह आतंकवाद चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं है कि हमें युद्ध पर उतरना पड़ेगा।

अब्दुल्ला ने कहा, यह आतंकवाद किसी की मदद नहीं करेगा। अगर वह मुल्क जो इनको भेज रहा है, हमारा पड़ोसी (पाकिस्तान) यह समझता है कि इससे कोई तब्दीली आएगी तो वह नहीं होगा। वे फेल हो जाएंगे। आज पांच जवानों ने शहादत दे दी है। पांच अस्पताल में गंभीर हैं। मुझे इससे तो डर है कि कहीं हम लोगों में लावा इतना भर जाए कि हमें लड़ाई पर आना पड़े। उनको ये देखना चाहिए। वे पहले ही बर्बाद हो गए हैं। लड़ाई दोनों मुल्कों में तबाही ही लाएगी। इसको बंद करें। आतंकवाद को बंद करें। सारी दुनिया में इसकी निंदा हो रही है।

उन्होंने कहा, कोई भी दुनिया का मुल्क इसको कबूल करने को तैयार नहीं है। ये जो कर रहे हैं इससे उनको मिलेगा क्या। आज उन जवानों के घरों में मातम हो रहा होगा। वे कह रहे होंगे कि आप क्यों बैठे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं। ये आतंकवाद उनको ही बर्बाद कर देगा। पाकिस्तान से बातचीत के रास्ते को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बातचीत भी होगी जब ये सब बंद होगा। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकतीं। वक्त आ गया है कि अगर हमें दोस्ती चाहिए तो उसकी राह बनानी होगी आतंकवाद उस रास्ते की तरफ नहीं है। उनको आतंकवाद पर सख्त कदम उठाने चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, आज ही नहीं सालों साल से हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। क्या वे चाहते हैं कि उनके घरों में भी मातम आए।

फारूक अब्दुल्ला ने कहा, मुझे समझ में नहीं आता कि उनकी (पाकिस्तान) सोच क्या है। इससे कोई भी आगे नहीं आएगा। इससे वे पीछ जाएंगे। देर होने से पहले उन्हें बंद करना चाहिए। पूरी दुनिया को इस देश पर दबाव बढ़ाना चाहिए और बताया चाहिए कि यह शांति का नहीं बल्कि तबाही का रास्ता है और इसको तुरंत बंद करना चाहिए।

बता दें कि सोमवार को कठुआ में सेना के काफिले पर आतंकियों के झुंड ने हमला कर दिया था। आतंकियों ने वाहनों को घेर लिया और फिर ग्रेनेड फेंकने शुरू कर दिए। घात लगाकर किए गए हमले में पांच जवान शहीद हो गए और पांच गंभीर रूप से घायल हो गए।

रूस जाने वाले संसदीय डैलिगेशन का नेतृत्व करेंगे ओम बिड़ला

नयी दिल्ली, 9 जुलाई (वार्ता) लोक सभा अध्यक्ष ओम बिड़ला रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में गुरूवार से शुरू होने वाले दो दिवसीय दसवें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे।

इस शिष्टमंडल में राज्य सभा के उपसभापति हरिवंश, राज्य सभा सदस्य शंभू शरण पटेल, लोक सभा के महासचिव, उत्पल कुमार सिंह और राज्य सभा के महासचिव पी.सी. मोदी शामिल हैं। लोक सभा सचिवालय में संयुक्त सचिव अंजनी कुमार शिष्टमंडल के सचिव हैं।

दसवें ब्रिक्स संसदीय मंच का मुख्य विषय 'समान वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करने में संसदों की भूमिका' है।

नाबालिग से ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

1.02 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि भले ही मामले में पीड़िता और उसके माता-पिता पक्षद्रोही हो गए हो, लेकिन डी.एन.ए. रिपोर्ट से साबित है कि अभियुक्त ने पीड़िता के साथ ज्यादती की है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ललिता संजीव महरवाल ने अदालत को बताया कि 2 जुलाई, 2023 को पीड़िता के पिता ने शास्त्रीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि कल शाम को उसकी पत्नी का फोन आया था कि पीड़िता दोपहर से नहीं मिल रही है। जब वह घर पहुंचा तो पत्नी ने बताया कि पीड़िता अपने छोटे भाई के साथ मदीना मस्जिद के आगे खेलने गई थी। इस दौरान दोनों बच्चों के बीच झगड़ा हो गया। इस पर बेटा तो घर आ गया, लेकिन बेटी घर नहीं आई। उसने पत्नी के साथ बेटी को आसपास तलाश किया, लेकिन उसका पता नहीं चला। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान पीड़िता और उसके माता पिता पक्षद्रोही हो गए, उन्होंने घटना से इनकार किया। लेकिन डी.एन.ए. रिपोर्ट में अभियुक्त का सीमन पीड़िता के कपड़ों पर पाया गया। इस पर अदालत ने अभियुक्त को दंडित करते हुए उस पर जुर्माना लगाया है।

'बिहार व बंगाल जैसे राज्यों में मुस्लिमों की आबादी अनियंत्रित तरीके से बढ़ रही है'

नई दिल्ली, 9 जुलाई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आर.एस.एस.) से जुड़ी एक पत्रिका ने देश के कुछ इलाकों में मुस्लिम आबादी बढ़ने के साथ 'जनसांख्यिकीय असंतुलन' बढ़ने का दावा करते हुए कहा कि एक व्यापक राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण नीति की जरूरत है। 'ऑर्गेनाइजर' साप्ताहिक के ताजा अंक में प्रकाशित संपादकीय में जनसंख्या के लिहाज से क्षेत्रीय असंतुलन पर चिंता जताते हुए नीतिगत हस्तक्षेप की वकालत की गई है।

पत्रिका में लिखा गया है कि पश्चिम और दक्षिण के राज्य जनसंख्या नियंत्रण उपायों को लागू करने में अपेक्षाकृत बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जनगणना के बाद आबादी में बदलाव होने पर संसद में कुछ सीट कम होने का डर है।

चार दिन में दूसरी बार राहुल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

साथ ही, एक सीट (कानपुर में सीसामऊ) इसलिये खाली हुई है कि उस सीट के विधायक को भ्रष्टाचार के एक केस में दोषी ठहराया गया है। अन्य सीटें, जहाँ उपचुनाव होने हैं, इस प्रकार हैं- प्रयागराज में फूलपुर, अलीगढ़ में खैर, गाजियाबाद शहर, मिर्जापुर में मझुआ, मुजफ्फरनगर में मीरपुर, फैजाबाद में मिल्कीपुर, मैनपुरी में करहल, अम्बेडकर नगर में कथेहरी तथा मुरादाबाद में कुन्द्रकी। वर्ष 2022 के चुनावों में, इनमें से पाँच सीटों पर भाजपा तथा उसके गठबंधन-पार्टनरों की जीत हुई थी तथा शेष पाँच सीटें इण्डिया गठबन्धन के खाते में गई थीं।

इन उपचुनावों के परिणामों का योगी आदित्यनाथ सरकार की स्थिरता पर कोई असर नहीं होगा। जैसा कि सामान्य ट्रैंड रहा है, राज्य के उपचुनावों में सत्तारूढ़ दल की ही विजय हुई है। फिर भी, इन उपचुनावों से एक बड़ी राजनैतिक प्रतीकात्मकता जुड़ी हुई है। एन.डी.ए. तथा इंडिया गठबन्धन इन सीटों को जीतने के लिये एडी-चोटी का जोर लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रत्येक सीट के लिये दो मन्त्री नियुक्त कर रखे हैं तथा योगी स्वयं भी उपचुनावों पर नजर रखे हुए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बी.एल.सन्तोष ने शनिवार और रविवार को लखनऊ में रहकर पार्टी के प्रान्तीय नेताओं के साथ आगे की योजनाएं सुनिश्चित कीं।

■ **क्योंकि मिल्कीपुर अयोध्या से सटी हुई सीट है और भाजपा इस सीट पर जीतती है तो उसकी अयोध्या में प्रतिष्ठा पुनः स्थापित हो जाती है जो फैज़ाबाद सीट पर लोकसभा चुनाव में हार के बाद काफी गिर सी गयी थी।**

इस बीच, पार्टी की राजनैतिक उपस्थिति बढ़ने से उत्साहित कांग्रेस पार्टी ने दो-तीन सीटों पर चुनाव लड़ने की माँग की है। कांग्रेस का तर्क है कि समाजवादी पार्टी उन सीटों पर चुनाव लड़ सकती है जो उसने स्वयं खाली की हैं तथा कांग्रेस को वे सीटें दी जा सकती हैं जो भाजपा या उसके सहयोगी दलों ने खाली की हैं। सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस ने तीन सीटें माँगी हैं - गाजियाबाद, फूलपुर तथा खैर। ऐसी सम्भावना है कि राहुल गांधी अगले कुछ दिनों में सपा नेता अखिलेश यादव के साथ सीट शेयरिंग योजना पर चर्चा करेंगे।

फैजाबाद की मिल्कीपुर सीट, जो अयोध्या चुनाव क्षेत्र से सटी हुई है, के लिये होने वाली राजनैतिक लड़ाई पर सबकी नजरें रहेंगी।

भाजपा मिल्कीपुर सीट को जीतने में अपनी सारी ताकत झौंक सकती है क्योंकि यह सीट भगवा पार्टी को उसका वह गर्व एवं सम्मान कुछ हद तक वापस पाने में मदद कर सकती है, जो उसने उस समय खो दिया थ, जब लोकसभा चुनावों में सपा ने फैजाबाद/अयोध्या सीट पर भगवा पार्टी को हरा दिया था लेकिन इस सीट पर होने वाली लड़ाई काफी कड़ी रहने की सम्भावना है क्योंकि अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर सीट लगातार सात बार जीत चुके हैं। भाजपा का मानना है कि इस बार चुनावी मैदान में बसपा की मौजूदगी से भाजपा को लाभ मिलेगा। सामान्यतः बसपा उपचुनाव नहीं लड़ा करती है लेकिन इस बार उसने चुनावी अखाड़े में उतरने की घोषणा कर दी है।

भारत-रूस संवाद से पहले...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ज्ञातव्य है कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद, जब वैश्विक ऊर्जा बाजार की खलबली जब अपने चरम पर थी, उस समय भारत को रूस से कम दरों पर तेल मिला था।

इसके अलावा, भारत का एक और भी हित था। भारत को रूस से हथियार लेने थे क्योंकि रूस परम्परागत रूप से उस समय भी भारत के लिये सैन्य हार्डवेयर का प्रमुख सप्लायर रहा है, जब पश्चिमी देशों ने भारत को हथियार देने से इनकार कर दिया था। अभी हाल ही में, भारत ने सैन्य हार्डवेयर की खरीद में कुछ बदलाव भी किए हैं।

इसीलिये, रूसी नेता से भेंट करने में भारत के बड़े हित निहित हैं। यह यात्रा जितनी भारत के लिए महत्वपूर्ण है, उतनी ही पुतिन के लिए भी, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री की रूस यात्रा ने पश्चिम को यह दर्शा दिया है कि रूस शेष विश्व से इतना अलग-थलग तथा कटा हुआ नहीं है, जितना पश्चिमी देश चाहते हैं।

■ **अतः मोदी का पुतिन को गले लगाना यह मैसेज भी दे रहा था कि भारत की विदेश नीति भारत के हितों पर निर्भर करती है केवल थ्योरैटिकल सिद्धांतों पर नहीं।**

दुनिया में चीन के अलावा ऐसा अन्य कोई देश नहीं है जो रूस को वैश्विक स्तर पर स्वीकृति दे रहा हो। इसके अलावा, इन्टरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा पुतिन के खिलाफ दिए गए गिरफ्तारी के फैसले के फलस्वरूप, रूस के बाहर की पुतिन की सारी गतिविधियां रुक गई हैं।

लेकिन, मोदी की रूस यात्रा के आस-पास की परिस्थितियों ने इस यात्रा को मोदी तथा भारत के लिए और ज्यादा जटिल तथा उत्तेजक बना दिया है। दरअसल, जिस दिन मोदी मॉस्को पहुँचे थे, रूस ने यूक्रेन के कीव शहर में बच्चों के अस्पताल पर हमला कर दिया था, जिसके फलस्वरूप अस्पताल में काफी बच्चों की मृत्यु हो गई थी।

मीटिंग का ब्यौरा जारी करते हुये, भारतीय पक्ष ने यह स्पष्ट कर दिया था कि बच्चों की मौतों के समाचार को लेकर प्रधानमंत्री ने गहरी वेदना एवं दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को भी रेखांकित किया था, कि भारतीय नागरिकों को धोखा देकर रूसी सेना में भर्ती कर लिया गया है तथा उन्हें यूक्रेन में युद्ध करने भेज दिया गया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन रूसी सेना भर्ती कर लिए गए इन भारतीयों को स्वदेश भेजने के लिए सहमत हो गए हैं।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908